the firm from 1971-72 onwards as under:—

Year	Indian Airlines	Air India
	Rs.	Rs.
1971-72	90,92,150·00	52,58,000·00
1972-73	24,14,464·62	26,92,000·00
1973-74	22,88,129·79	39,77,000·00
1974-75	57,18,915·93	73,20,000·00
1975-76	97,78,976·40	1,15,79,000·00
1976-77	1,08,14,298·48	1,12,19,000·00
1977-78	1,77,08,991·40	2,55,67,000·00
1978—Jan. 79	57,80,255·64	2,20,28,000·00

Merger of Agriculture Finance Corporations with Agriculture Refinance Corporations

6300. SHRI VAYALAR RAVI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have got any plans to merge the Agriculture Finance Corporations with the Agriculture Refinance Corporations; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA): (a) and (b) No, Sir. However, the Reserve Bank of India have constituted a committee to review the existing arrangements for institutional credit for agricultural and rural development, including operations of Agricultural Refinance and Development Corporation and the services provided by the Agricultural Finance Corporation.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वैच्छिक घोषणाओं के लिए बाण्डों का जारी किया जाना

6302. श्री बुधराम : क्या वित्त राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से काले धन की घोषणा की थी, उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनेक बाण्ड अब भी बैंक के पास पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इन बाण्डों पर 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा ;

(ग) क्या दो महीने की अवधि के भीतर इन बाण्डों को न लेने की स्थिति में इन बाण्डों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा ; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने काले धन की घोषणा की है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की घोषणा की गई है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक बाण्ड नहीं लिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). 5 3/4 प्रतिशत बांड, 1985 इस उद्देश्य से जारी किये गए थे कि वाणिज्यिक

(डिक्लेरेण्ट्स) आय और सम्पत्ति का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (जिसे 1976 में संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था) की धारा 3(1) के अन्तर्गत स्वेच्छा से अपनी आय को तथा उक्त अध्यादेश की धारा 15(1) के अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति को प्रकट कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने 2½ लाख से अधिक बाण्ड जारी किए थे जिनमें से केवल बहुत कम प्रतिशत भाग मुख्यत: औपचारिकताएं पूरा नहीं किये जाने के कारण निवेशकों ने अब तक नहीं लिये हैं।

धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रकट किये गए ब्यौरे गोपनीय हैं और धारा 12 के अंतर्गत उनको बताने की मनाही है। धारा 3(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं को छोड़कर जो अन्य घोषणाएं की गई हैं वे 17 हजार से अधिक हैं। मांगी गई सूचना को इकट्ठा करने में जो बहुत अधिक प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जी, हां। जिस तारीख को बांड जारी किये गए हैं अर्थात् जिस तारीख को निवेश किये गये हैं उस तारीख से उन पर ब्याज देय है।

(ग) जी, नहीं।

Distribution of Imported Edible Oils

6303. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) what is the quantity of edible oils to be imported this year through S.T.C and bther private parties;

(b) the mode of distribution to ensure that even the far-flung areas are also served according to their demands; and

(c) the names of private parties importing this oil and what shall be their disposal of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) to (c). The import of all edible oils/oilseeds has been canalised through S.T.C. with effect from 2-12-1978. The quantity of edible oils to be imported during 1979-80 by the S.T.C. would be determined from time to time in the context of the various relevant factors including demand and indigenous availability of oils. As regards the distribution, the requirements of imported edible oils by the vanaspati industry and by the State Governments for issue through Public Distribution System are already being met satisfactorily through the S.T.C. As regards the other consumers, the present arrangement envisages supply of oils/seeds by the S.T.C. after import, to the private refiners/crushers for sale through the normal trade channels.

With the canalisation of imports through S.T.C. the import by private parties has been discontinued except against certain firm commitments entered into by some of them prior to 2.12.78. How much would actually be so imported by which party during 1979-80 is not known, but the quantum of such imports is likely to be not much. There is no control imposed on the distribution of oils imported by private parties.

Traders Seeking Permissions for Export of Silver

6304. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether scores of silver traders are running from pillar to post seeking permissions to export hundreds of tonnes of silver orders for which were booked prior to Government ban on exports;